

अफीम का मूल्य

1108. श्री राम सेबक यादव :
 श्री महाराज सिंह भारती :
 श्री जार्ज फरमैन्टोस :
 श्री मोल्लू प्रसाद :
 श्री मधु लियवे :
 श्री रवि राय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1965-66 से 1966-67 तक की अवधि में सम्पूर्ण देश में चोरी छिपे साये ले जाये गये अफीम की कितनी मात्रा पकड़ी गई;

(ख) क्या यह सच है कि अफीम की तस्करी किये जाने का एक कारण यह भी कि किसानों को अफीम की कीमत कम दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या किसानों को अफीम की दी जाने वाली कीमत में वृद्धि करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कैम्बेडर वर्ष 1965, 1966 में तथा 27 मई 1967 तक एक देश में चोरी-छिपे साईं ले जाई गई अफीम की निम्नलिखित मात्रा पकड़ी गई:—

वर्ष	पकड़ी गई मात्रा (किलोग्राम)
1965	5,229
1966	7,945
1967	507

(27 मई तक)

(ख) चोरी छिपे देधी जानी वाली अवैध अफीम का मूल्य, सरकार द्वारा

किसानों से खरीदी गई अफीम के मूल्य से बहुत अधिक होता है और मूल्यों की यह असमानता ही तस्कर व्यापार को प्रोत्साहन देती है।

(ग) किसानों को दिया जाने वाला मूल्य, प्रत्येक वर्ष, अन्य कृषि उत्पादों के मू-य-साम्य को ध्यान में रखकर नियत किया जाता है और इसी प्रकार वह मूल्य भी निश्चित किया जाता है जिस पर सरकार विदेशों में अफीम बेच सकती है। इसलिये, मूल्य में विशेष वृद्धि करना व्यवहार्य नहीं है, और यदि प्रयत्न किया भी जाय तो तस्करों द्वारा अवैध रूप से माल लेने देने के दामों से मुकाबला नहीं किया जा सकता। सदा की भांति, प्रगती फसल के शुरू होने से पूर्व जुलाई अगस्त 1967 में मूल्य की समीक्षा की जायेगी।

Association of Businessmen and Technicians in Public Sector Undertakings

1110. Shri S. R. Damani:
 Shri Kartik Oraon:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to associate experienced businessmen and technicians in the private sector with the public sector undertakings in order to avail of their matured business experience; and

(b) if so, the nature thereof?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) and (b) It is the practice of Government to draw available talents from all sources, including the Private Sector, to man posts of Directors, as well as those of top management which are reserved for appointment by Government. There is, therefore, no question of any fresh proposal in this respect being considered.